बुधवार
09 सितम्बर 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 228
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94 email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

एक प्रकरण, तीन एफआईआर

◆उत्तराखंड में सियासत से सड़क तक पहुंचा विवाद
◆3 एफआईआर के कानूनी जाल में उलझा विवाद
◆कांग्रेस का हल्लाबोल तो भाजपा का पलटवार
◆सामाजिक मर्यादा बनाम राजनीतिक दांव-पेच

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में हल्द्वानी के कथित शुद्धिकरण प्रकरण ने अब नया मोड़ ले लिया है। एक आयोजन से शुरू हुआ विवाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर तीन अलग-अलग एफआईआर तक पहुंच गया है। मामला जितना कानूनी होता जा रहा है, उतना ही इसका राजनीतिक तापमान भी बढ़ रहा है। कांग्रेस जहां इसे सामाजिक सौहार्द और राजनीतिक मर्यादा से जोड़कर सरकार को घेर रही है, वहीं भाजपा इसे कांग्रेस की राजनीतिक बेचैनी और मुद्दाविहीनता से जोड़ने की कोशिश कर रही है।

हल्द्वानी में कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम के बाद विवाद ने तेजी पकड़ी। कार्यक्रम को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए और देखते ही देखते मामला राजनीतिक मुद्दा बन गया। आरोप-प्रत्यारोप के बीच पुलिस तक शिकायतें पहुंचीं और प्रकरण में तीन एफआईआर दर्ज होने से विवाद की गंभीरता बढ़ गई। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह गया कि कार्यक्रम में क्या हुआ था, बल्कि सवाल यह भी है कि इस पूरे प्रकरण में कानून-व्यवस्था, राजनीतिक जिम्मेदारी और सामाजिक सौहार्द की सीमाएं कहां तय होंगी?

एक ही विवाद से जुड़े घटनाक्रम में तीन एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक दलों के लिए पीछे हटना मुश्किल होता जा रहा है। कांग्रेस इसे अपने खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई के रूप में देख रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एफआईआर की संख्या ने इस प्रकरण को सामान्य राजनीतिक बयानबाजी से निकालकर कानूनी जांच के दायरे में ला दिया है। अब आरोपों की राजनीतिक व्याख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण पुलिस जांच और उसके निष्कर्ष होंगे।

कांग्रेस ने मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध-प्रदर्शनों ने इसे प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस का प्रयास है कि इस प्रकरण को व्यापक सामाजिक और राजनीतिक सवाल से जोड़कर भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन कांग्रेस के सामने भी चुनौती है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि आंदोलन कानूनी और लोकतांत्रिक विरोध की सीमा में रहे, ताकि मुद्दा मूल विवाद से हटकर कानून-व्यवस्था के सवाल में न बदल जाए।

भाजपा के सामने भी इस विवाद को संभालने की चुनौती कम नहीं है। सत्ता पक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस कार्रवाई निष्पक्ष दिखाई दे और किसी भी पक्ष को यह संदेश न जाए कि राजनीतिक दबाव जांच को प्रभावित कर रहा है। भाजपा यदि इस मामले को केवल कांग्रेस बनाम भाजपा के राजनीतिक संघर्ष के रूप में पेश करती है तो सामाजिक स्तर पर उठ रहे सवाल पीछे छूट सकते हैं। उसे यह स्पष्ट करना होगा कि कानून सबके लिए समान है और धार्मिक-सामाजिक भावनाओं से जुड़े मामलों में राजनीतिक संयम जरूरी है।

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। इसलिए इसकी राजनीतिक गूंज आने वाले महीनों में और बढ़ सकती है। कांग्रेस इसे सरकार के खिलाफ बड़े नैरेटिव में बदलने की कोशिश करेगी, जबकि भाजपा इसे कांग्रेस की रणनीति और राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़ सकती है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक दल नहीं, उत्तराखंड का सामाजिक ताना-बाना है। देवभूमि की राजनीति में धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता हमेशा महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में किसी भी तरह के कथित शुद्धिकरण, बहिष्कार या अपमान से जुड़े घटनाक्रम को राजनीतिक लाभ के लिए और भड़काना दोनों पक्षों के लिए नुकसानदेह हो

सकता है। तीन एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अब जनता की नजर इस बात पर है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और आरोपों की सच्चाई क्या सामने आती है। राजनीतिक मंचों पर बयानबाजी जारी रहेगी, लेकिन कानून का फैसला राजनीतिक नारों से नहीं, साक्ष्यों और जांच से होना चाहिए। एक घटना, तीन एफआईआर और बढ़ता राजनीतिक तापमान। हल्द्वानी का यह प्रकरण अब सिर्फ स्थानीय विवाद नहीं रह गया है। यह 2027 की चुनावी राजनीति में सामाजिक सौहार्द, कानून-व्यवस्था और राजनीतिक संयम की भी परीक्षा बनता दिखाई दे रहा है।

बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली

हमारे संवाददाता

नैनीताल। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज प्रस्तावित अहम सुनवाई फिलहाल टल गई। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नई तारीख निर्धारित की है। इससे पहले भी विभिन्न तारीखों पर सुनवाई स्थगित हो चुकी है, जिसके चलते आज की कार्यवाही को लेकर क्षेत्रवासियों और प्रशासन की नजरें टिकी थीं। वहीं, सुनवाई को लेकर नैनीताल पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर रही। बनभूलपुरा क्षेत्र में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती के साथ ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई। इसके अलावा पुलिस टीमों ने क्षेत्र में चेकिंग और फ्लैग मार्च कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। पुलिस ने लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सोशल मीडिया पर अफवाह, भ्रामक अथवा भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने से बचने की चेतावनी दी। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दून वैली मेल

संपादकीय

रैंकिंग नहीं, सांसों की गुणवत्ता जरूरी

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शहरों की रैंकिंग सामने आते ही नगर निकायों और सरकारों के लिए अपनी पीठ थपथपाने का दौर शुरू हो जाता है। कहीं बेहतर प्रदर्शन की उपलब्धि गिनाई जाती है तो कहीं पिछड़ने के कारण खोजे जाते हैं। लेकिन असली सवाल रैंकिंग का नहीं, शहर में रहने वाले नागरिक को वास्तव में कितनी साफ हवा मिल रही है, इसका है। स्वच्छ हवा अब सुविधा नहीं, जीवन की बुनियादी जरूरत है। बढ़ता यातायात, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल, सड़क किनारे कूड़े का जलना, औद्योगिक गतिविधियां और हरित क्षेत्र का लगातार सिकुड़ना हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। समस्या यह है कि प्रदूषण दिखाई न देने पर भी उसका असर लगातार शरीर और पर्यावरण पर पड़ता रहता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की सबसे बड़ी उपयोगिता तभी है, जब इसे केवल पुरस्कार और प्रमाणपत्र हासिल करने की प्रतियोगिता न बनाया जाए। सर्वेक्षण से मिले आंकड़ों को शहर की वास्तविक समस्याओं से जोड़ना होगा। यदि किसी शहर की रैंकिंग सुधरती है लेकिन उसके प्रमुख चौराहों पर धूल, धुआं और जाम जस के तस हैं, तो यह सफलता अधूरी है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए यह सवाल और गंभीर है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी और ऊधमसिंह नगर के तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच हवा की गुणवत्ता को लेकर दीर्घकालिक नीति जरूरी है। पहाड़ों को यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि जंगल और हरियाली होने मात्र से प्रदूषण का खतरा समाप्त हो जाता है। पर्यटन, वाहनों की बढ़ती संख्या, निर्माण और कचरा प्रबंधन की कमजोरियां यहां भी चुनौती बन रही हैं। जरूरत केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई की नहीं, बल्कि नगर नियोजन की पूरी सोच बदलने की है। सार्वजनिक परिवहन मजबूत हो, पैदल और साइकिल के लिए सुरक्षित रास्ते बनें, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण अनिवार्य हो, कूड़ा जलाने पर प्रभावी रोक लगे और शहरों में हरित क्षेत्र सुरक्षित किए जाएं। साथ ही वायु गुणवत्ता के आंकड़े नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध और समझने योग्य होने चाहिए। सरकारों को यह भी समझना होगा कि स्वच्छ हवा का सवाल किसी एक विभाग का विषय नहीं है। नगर निकाय, परिवहन, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग और शहरी विकास एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। सड़क चौड़ी करने से पहले यह सोचना होगा कि उससे यातायात सुधरेगा या कुछ वर्षों बाद वाहनों और प्रदूषण का नया संकट खड़ा होगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रैंकिंग शहरों को आईना दिखाने का काम करती है। इस आईने में केवल अपनी तस्वीर देखकर खुश होने के बजाय उन कमियों को देखना होगा, जिन्हें नागरिक रोज अपनी सांसों के साथ महसूस कर रहे हैं। आखिरकार किसी शहर की असली उपलब्धि यह नहीं कि वह सर्वेक्षण में कितने नंबर पर आया। असली सफलता तब होगी, जब बच्चे बिना प्रदूषण के डर के खेल सकें, बुजुर्ग खुली हवा में सांस ले सकें और आम नागरिक को यह महसूस हो कि उसके शहर की हवा सचमुच बेहतर हुई है। रैंकिंग बदलती रहती है, लेकिन साफ हवा की जरूरत हर दिन रहती है।

मकान का ताला तोड जेवरात चोरी

संवाददाता

देहरादून। चोरों ने मकान का ताला तोड वहां से जेवरात चोरी कर लिये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार तिलक रोड निवासी संजय गोयल ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह परिवार के साथ बाहर गया था आज जब वह वापस आया तो उसने देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ था तथा अन्दर सारा सामान बिखरा हुआ था। चोर उसके यहां से अलमारी में रखे जेवरात चोरी करके ले गये हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन

संवाददाता

देहरादून। जिला योजना समिति के सदस्य निर्वाचन-2026 के संबंध में नगर निकायवार एवं जिला पंचायतवार निर्वाचक नामावलियों के परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 के आलेख्य का प्रकाशन कर दिया गया है। आज यहां जिला योजना समिति के सदस्य निर्वाचन-2026 के संबंध में नगर निकायवार एवं जिला पंचायतवार निर्वाचक नामावलियों के परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 के आलेख्य का प्रकाशन कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, देहरादून की अधिसूचनाख्या 685/ रा०नि०आ०- 03/1452/2023, 02 सितंबर 2026 तथा इस कार्यालय की सूचना संख्या 287, 05 सितंबर 2026 के क्रम में उक्त आलेख्य प्रकाशित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग अधिकारी डा.आशीष चौहान ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का अवलोकन कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी एवं आवश्यक दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है।

नशे के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की जीआईएस मैपिंग कर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश

संवाददाता

देहरादून। अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्रीमती स्मृता परमार ने पुलिस विभाग को जनपद के नशा प्रभावित एवं संवेदनशील हॉटस्पॉट क्षेत्रों की जीआइ

आज यहां जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्रीमती स्मृता परमार की अध्यक्षता में एनडीपीएस एक्ट, 1985 में वर्णित प्राविधानों/नियमों के अंतर्गत अफीम खस-खस एवं पोस्त की खेती तथा ड्रग्स के उपयोग को पूर्णत: रोकने एवं संबंधित क्रियान्वयन के संबंध में जिला स्तरीय समिति (एनकॉर्ड) की बैठक अपर जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार एवं नशे के बढ़ते प्रचलन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशा केवल कानून-व्यवस्था से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ी गंभीर चुनौती है। इसके लिए प्रवर्तनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया जाना आवश्यक है।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को समन्वित रूप से मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियमित रूप से कार्यशालाएं, जागरूकता कार्यक्रम एवं संवाद सत्र आयोजित किए जाएं, ताकि छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों एवं इससे बचाव के उपायों की जानकारी दी जा सके। पुलिस विभाग को जनपद के नशा प्रभावित एवं संवेदनशील हॉटस्पॉट क्षेत्रों की जीआईएस मैपिंग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ऐसे क्षेत्रों की नियमित निगरानी करते हुए नशे के अवैध कारोबार एवं मादक पदार्थों के क्रय-विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं आबकारी विभाग को पोस्त की खेती पर प्रभावी प्रतिबन्ध हेतु सम्बन्धित क्षेत्रो में नियमित छापेमारी के निर्देश दिए गए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई के साथ-साथ नशे की गिरफ्त में आए व्यक्तियों को चिन्हित कर आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य एवं सामाजिक पुनर्वास से संबंधित सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में भी विभागीय समन्वय से कार्य किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को निरंतर, प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाया जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने स्तर पर की जा रही कार्रवाई एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करने तथा आपसी समन्वय से ठोस कार्ययोजना के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी अंकित कंडारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, आबकारी निरीक्षण शिव प्रसाद व्यास सहित शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

चुनावी कसौटी पर उत्तराखंड

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की जमीन तैयार होने लगी है और इसके साथ ही सियासी मुकाबले का सबसे बड़ा सवाल भी आकार लेने लगा है कि भाजपा अपने पांच साल के शासन का हिसाब लेकर जनता के बीच जाएगी या कांग्रेस पांच साल की विपक्षी राजनीति को सत्ता की सीढ़ी बनाएगी? चुनाव में अब मुद्दों से ज्यादा यह कसौटी महत्वपूर्ण होगी कि जनता किसके दावों को अपने अनुभव के करीब पाती है। सत्तारूढ़ भाजपा के पास सबसे बड़ा हथियार सरकार का रिपोर्ट कार्ड होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी विकास परियोजनाओं, सड़क और कनेक्टिविटी, निवेश, रोजगार, महिला कल्याण, कानून-व्यवस्था और धार्मिक-आध्यात्मिक स्थलों के विकास को अपनी उपलब्धियों के रूप में जनता के सामने रखने की तैयारी में है।

भाजपा की रणनीति साफ है सरकार ने क्या किया, इसे बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए। पार्टी का संगठनात्मक ढांचा उसके अभियान की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यदि भाजपा सरकार की योजनाओं और उनके वास्तविक लाभार्थियों को चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाने में सफल रही तो विपक्ष के आरोपों की धार कमजोर करने में उसे मदद मिलेगी। लेकिन सत्ता के साथ जवाबदेही भी आती है। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, पहाड़ों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति, सरकारी भर्तियों और स्थानीय स्तर पर विकास की गति जैसे सवालों पर भाजपा को विपक्ष के साथ-साथ जनता के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा।

◆धामी के रिपोर्ट कार्ड से खिलेगा कमल या कांग्रेस बनाएगी सत्ता की राह
◆बीजेपी के काम का हिसाब बनाम कांग्रेस की 5 साल की घेराबंदी
◆दावों से नहीं, जनता के अनुभव से तय होगी 2027 की सरकार
◆शासन बनाम पांच साल की विपक्षी राजनीति, जनता मांगेगी हिसाब

कांग्रेस की चुनौती और अवसर दोनों यहीं से शुरू होते हैं। विपक्ष के पास सरकार चलाने का पांच साल का रिकार्ड नहीं है, लेकिन उसके पास सरकार से पांच साल सवाल पूछने का रिकार्ड जरूर है। कांग्रेस बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं, महंगाई, पलायन, किसानों की समस्याओं, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दों को चुनावी हथियार बनाने की कोशिश करेगी। पार्टी का तर्क होगा कि सरकार के दावों और जमीन पर जनता के अनुभव में अंतर है। लेकिन कांग्रेस के सामने भी बड़ा सवाल है कि पांच साल विपक्ष में रहते हुए उसने जनता के बीच कितनी मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार की? सिर्फ सरकार की कमियां गिनाना पर्याप्त नहीं होगा। कांग्रेस को यह भी बताना पड़ेगा कि सत्ता में आने पर वह क्या अलग करेगी। 2027 का चुनाव उसके लिए केवल भाजपा विरोध का चुनाव नहीं, बल्कि वैकल्पिक शासन माडल पेश करने की परीक्षा भी होगा।

उत्तराखंड का चुनाव हमेशा केवल बड़े राजनीतिक नारों से तय नहीं होता। पहाड़ में सड़क कब पहुंची, अस्पताल में डाक्टर है या नहीं, स्कूल में शिक्षक हैं या नहीं, युवा को रोजगार मिला या नहीं और गांव से पलायन रुका या नहीं कि यह सवाल ज्यादा वजन रखते हैं। यही वजह है कि 2027 में सरकारी विज्ञापन बनाम विपक्षी आरोप की लड़ाई से आगे बढ़कर जमीन पर काम और जनता के अनुभव का मुकाबला होगा। भाजपा कहेगी कि उसने उत्तराखंड को नई दिशा दी, कांग्रेस कहेगी कि सरकार के दावे धरातल पर कमजोर हैं। जनता के सामने असली सवाल होगा कि इन दोनों दावों में सच्चाई कितनी है।

राज्य की 70 विधानसभा सीटों का चुनाव एक जैसा नहीं होगा। कुमाऊं और गढ़वाल, मैदान और पहाड़ तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे अलग-अलग हैं। कहीं सड़क और रोजगार बड़ा सवाल होगा तो कहीं वन कानून, जमीन, पर्यटन, कृषि और पलायन। ऐसे में दोनों दलों को प्रदेशव्यापी नैरेटिव के साथ विधानसभा स्तर का अलग चुनावी एजेंडा तैयार करना पड़ेगा। आखिरकार 2027 का चुनाव केवल भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं होगा। यह भाजपा के पांच साल के शासन और कांग्रेस के पांच साल के विपक्षी प्रदर्शन की संयुक्त परीक्षा भी होगा। भाजपा को बताना होगा कि उसने सत्ता में रहते हुए क्या बदला और कांग्रेस को साबित करना होगा कि वह सत्ता में आने के बाद क्या बदलेगी।

यही वह मोड़ होगा जहां चुनावी भाषणों से ज्यादा जनता का अपना अनुभव निर्णायक बनेगा। सरकार अपने काम का हिसाब देगी, विपक्ष अपने संघर्ष का, लेकिन अंतिम फैसला उत्तराखंड की जनता करेगी कि उसे अगले पांच साल के लिए किसकी कहानी पर भरोसा है।

एक्स-रे स्क्रीनिंग में प्रदेश में तीसरे स्थान पर पहुंचा अल्मोड़ा

अल्मोड़ा(आरएनएस)। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अल्मोड़ा जनपद में स्क्रीनिंग अभियान को तेज गति मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने एक्स-रे स्क्रीनिंग और एनएएटी जांच का दायरा बढ़ाते हुए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया है। इसके परिणामस्वरूप जनपद एक्स-रे स्क्रीनिंग के मामले में प्रदेश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरीश चंद्र पंत, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. प्रांशु डेनियल तथा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. दीपक शर्मा के नेतृत्व में अभियान का संचालन किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार की ओर से निर्धारित 547 हाई-रिस्क गांवों में हैंड हेल्ड एक्स-रे शिविर लगाने का लक्ष्य जनपद ने शत-प्रतिशत पूरा कर लिया है, जबकि एक्स-रे स्क्रीनिंग का कार्य लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1,97,226 लोगों की स्क्रीनिंग के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 1,12,313 लोगों का निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण किया जा चुका है, जबकि 59,780 लोगों की एक्स-रे स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर अल्मोड़ा वर्तमान में राज्य में तीसरे स्थान पर है और इस उपलब्धि को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान आरोग्य केंद्रों में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को भी निर्देशित किया है कि वे एनसीडी कार्यक्रम के तहत जांच के लिए आने वाले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान करने वाले तथा गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच के साथ आवश्यकता अनुसार बलगम परीक्षण और एक्स-रे स्क्रीनिंग भी सुनिश्चित करें। विभाग का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों की समय पर जांच कर टीबी मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों को शीघ्र हासिल करना है।

वरिष्ठ नागरिकों ने गिनाई शहर की समस्याएं

हल्द्वानी(आरएनएस)। नगर निगम सभागार में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की बैठक वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष नवीन वर्मा और एडीएम विवेक राय की संयुक्त अध्यक्षता में हुई। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन और अन्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।वरिष्ठ नागरिकों ने बताया कि नहर कवरिंग रोड पर कालटैक्स से आईटीआई तक करीब सात किलोमीटर लंबे मार्ग में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। इससे राहगीरों और विशेष रूप से बुजुर्गों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने की मांग की। वरिष्ठ नागरिकों ने बीट पुलिस की नियमित विजिट, आपातकालीन व्यवस्था, पुलिस विभाग में नोडल अधिकारी की तैनाती, शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने, सुगम आवागमन, सार्वजनिक स्वच्छता और शौचालय व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए।जिला प्रशासन से वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया। एडीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने कहा कि जो वरिष्ठ नागरिक अकेले रहते हैं, वे संबंधित थाने में अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराएं। आपात स्थिति में 112 पर संपर्क किया जा सकता है। बैठक में समिति अध्यक्ष भुवन भाष्कर पांडे, डीके पांडे, एसडीएम मोनिका, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुलेखा बिष्ट समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

'सामाजिक समरसता से खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस'

चम्पावत(आरएनएस)। चम्पावत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर सामाजिक समरसता से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए धरना दिया। गांधी चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सौहार्द संकल्प धरना दिया। भाजपा एससी मोंचा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस विभाजनकारी और तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने राजनीतिक हितों के लिए प्रदेश की सामाजिक समरसता और शांति से खिलवाड़ कर रही है, जिसे देवभूमि की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। कहा कि आने वाले चुनाव में आम जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी की घटना के बाद जिस तरह से कांग्रेस शुद्धिकरण की राजनीति को लेकर समाज में भ्रम फैला रही है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उत्तराखंड के शांत वातावरण में जातिवाद का जहर घोल रही है। भाजपा देवभूमि की एकता और सामाजिक सौहार्द को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देगी। धरना कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत, जिपं अध्यक्ष आनंद अधिकारी, दर्जाधारी श्याम पांडेय, सुभाष बगौली, मुकेश महराना, मनोज कालाकोटी, रोहित बिष्ट व किरन देवी, प्रमुख अंचला बोहरा, पालिकाध्यक्ष प्रेमा पांडेय, प्रदेश महामंत्री एससी मोर्चा दर्पण कुमार, पूर्व दर्जाधारी अजय राजौरपूर्व विधायक पूरन फर्त्याल, शंकर पांडेय, प्रकाश तिवारी, मुकेश कलखुड़िया, सुनील पुनेठा, गौरव पांडेय, पारस महर, कैलाश अधिकारी, राजू बिष्ट, अजय नरियाल, कपिल खर्कवाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

चुनाव 'पास' और मुद्दे 'गायब'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड चुनावी मोड में पहुंच चुका है और सियासत का पारा चढ़ने लगा है। लेकिन प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा जगह घेर रखी है, वह रोजगार नहीं, पलायन नहीं, अस्पताल नहीं, सड़क नहीं और आपदा नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। हल्द्वानी में कथित मंच शुद्धिकरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस जिस तरह आमने-सामने हैं, उससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उत्तराखंड के असली मुद्दे राजनीतिक दलों के लिए अब इतने छोटे हो गए हैं कि उन्हें चुनावी शोर में दबाया जा सके? एक तरफ कांग्रेस इस घटनाक्रम को सामाजिक सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़कर सरकार पर हमला बोल रही है।

दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस पर विवाद को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रही है। बयान पर बयान, प्रदर्शन पर प्रदर्शन और पलटवार पर पलटवार जारी है। यानी चुनावी मैदान तैयार हो रहा है और दोनों दलों के पास एक-दूसरे को घेरने के लिए नया हथियार भी मिल गया है। लेकिन इसी बीच पहाड़ का वह युवा कहां है जो नौकरी की तलाश में देहरादून, दिल्ली, चंडीगढ़ या मुंबई जाने को मजबूर है? वह किसान कहां है जिसे अपनी उपज का उचित बाजार चाहिए? वह पहाड़ी परिवार कहां है जिसके गांव में अस्पताल तो दूर, डॉक्टर तक नियमित नहीं पहुंचता? वह आपदा प्रभावित परिवार कहां है जिसका घर बरसात में उजड़ जाता है और मुआवजे के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं?इन सवालों का शुद्धिकरण की राजनीति में जवाब नहीं है।

उत्तराखंड की राजनीति का यह सबसे बड़ा विरोधाभास है। चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दल जनता की भावनाओं से जुड़े प्रतीकों और विवादों को तेजी से पकड़ लेते हैं। कारण साफ है कि ऐसे मुद्दे तत्काल राजनीतिक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, समर्थकों को लामबंद करते हैं और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आसानी से दिखाई देते हैं। इसके मुकाबले बेरोजगारी पर बहस कठिन है। पलायन पर बहस में आंकड़े चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार और विपक्ष दोनों को अपना रिकॉर्ड सामने रखना पड़ेगा। स्कूलों की स्थिति पर सवाल उठेंगे तो घोषणाओं और जमीन की हकीकत का फर्क सामने आएगा। आपदा प्रबंधन पर सवाल होंगे तो हर साल बारिश में होने वाली तबाही का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए शायद शुद्धिकरण पर लड़ना आसान है और व्यवस्था के शुद्धिकरण पर बहस करना मुश्किल।

सत्तारूढ़ भाजपा के लिए यह केवल विपक्ष के आरोपों का जवाब देने का मामला नहीं है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने शासन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की है। सरकार को बताना होगा कि रोजगार के मोर्चे पर पिछले वर्षों में कितने स्थायी अवसर बने। कितने युवाओं को पहाड़ में ही रोजगार मिला। पलायन प्रभावित गांवों की तस्वीर कितनी बदली। स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना सुधार हुआ। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क और शिक्षा की

◆उत्तराखंड में पलायन और सड़कों पर भारी पड़ा मंच शुद्धिकरण का शोर
◆भाजपा और कांग्रेस की जंग में जनता के असली सवाल हो गए अशुद्ध
◆रोजगार, पलायन, आपदा, स्वास्थ्य और पहाड़ की बदहाली पर खामोशी

स्थिति कितनी बेहतर हुई। सिर्फ योजनाओं की घोषणा से चुनाव नहीं जीता जाता। जनता अब घोषणा नहीं, परिणाम पूछेगी। भाजपा यदि हर विवाद को कांग्रेस की राजनीति बताकर खारिज करती है तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जनता के मूल सवालों से उसका संवाद मजबूत रहे।

विपक्षी कांग्रेस के लिए भी रास्ता आसान नहीं है। सरकार को घेरने के लिए मुद्दा उठाना उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह शुद्धिकरण विवाद से आगे निकलकर अपना व्यापक राजनीतिक एजेंडा जनता के सामने रख पाएगी? कांग्रेस को बताना होगा कि सत्ता में आने पर वह रोजगार कैसे पैदा करेगी। पलायन रोकने के लिए उसकी नीति क्या होगी। पहाड़ की अर्थव्यवस्था को किस माडल से मजबूत करेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलेगा। सिर्फ भाजपा विरोध चुनावी विकल्प नहीं बनाता, विकल्प के लिए अपना रोडमैप भी चाहिए। यही वह जगह है जहां कांग्रेस को भावनात्मक मुद्दों के साथ ठोस नीतिगत मुद्दों को भी बराबर ताकत से उठाना होगा।

दरअसल यह विवाद सिर्फ एक मंच या शुद्धिकरण तक सीमित नहीं है। इसके पीछे 2027 की चुनावी राजनीति में नैरेटिव पर कब्जे की लड़ाई दिखाई दे रही है। भाजपा चाहती है कि चुनावी चर्चा सरकार के काम, विकास योजनाओं और उसके संगठनात्मक प्रदर्शन के इर्द-गिर्द रहे। कांग्रेस सत्ता विरोधी माहौल को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के जरिए धार देना चाहती है। दोनों दलों को पता है कि चुनाव केवल आंकड़ों से नहीं, धारणा से भी जीते जाते हैं। यही कारण है कि आने वाले महीनों में ऐसे विवादों की संख्या बढ़ सकती है जो राजनीतिक रूप से तुरंत असर पैदा करते हैं।लेकिन इस नैरेटिव की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान तब होगा, जब जनता के वास्तविक सवाल पीछे छूट जाएंगे।

राजनीतिक दल एक-दूसरे के मंचों और कार्यक्रमों की शुद्धता पर सवाल उठा रहे हैं। मगर उत्तराखंड की जनता इससे बड़ा सवाल पूछ सकती है कि राजनीति का शुद्धिकरण कब होगा? भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कब होगी? भर्ती परीक्षाओं पर भरोसा कब मजबूत होगा? पहाड़ से पलायन कब रुकेगा? सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डाक्टर कब मिलेंगे?दूरस्थ गांवों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब पहुंचेगी? बरसात में हर साल सड़कें टूटने और गांवों के अलग-थलग पड़ने का स्थायी समाधान कब होगा? और सबसे बड़ा सवालकृ कि जिस पहाड़ को बचाने के नाम पर हर चुनाव में राजनीति होती है, उस पहाड़ में रहने वाले युवाओं का भविष्य कौन बचाएगा?

सबसे बड़ा सवाल : भाजपा और कांग्रेस चाहे जितनी जोर से एक-दूसरे के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ें, लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार है कि वह दोनों से पूछेकृआपकी लड़ाई किसके लिए है?यदि लड़ाई केवल एक-दूसरे को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए है तो जनता के सवाल फिर अनुत्तरित रह जाएंगे। उत्तराखंड को ऐसी राजनीति चाहिए जो मंच के शुद्धिकरण से आगे बढ़कर व्यवस्था के शुद्धिकरण की बात करे। ऐसी राजनीति चाहिए जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विवादों पर अपनी राय रखे, लेकिन साथ ही रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा जैसे सवालों से आंख न चुराए। क्योंकि चुनाव मंच कौन साफ करता है, इस पर नहीं प्रदेश की व्यवस्था कौन साफ करेगा, इस पर होना चाहिए और अगर भाजपा-कांग्रेस की सियासी जंग में जनता के सवाल ही गायब हो जाएं, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है।

पूर्व विधायक प्रत्याशी समेत 238 से अधिक भाजपा-यूकेडी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल

अल्मोड़ा(आरएनएस)। जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव-2027 से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। विकासखंड लमगड़ा के चायखान स्थित वन विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा और उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) से जुड़े पूर्व विधायक प्रत्याशी शंकर लाल टम्टा समेत 238 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने किया। कांग्रेस में शामिल होने वालों का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष दीवान सतवाल ने किया। इस दौरान भाटकोट, भांगादेवली, नाटाडोल, मलाड़ी, ढैली, बलमा, नौरा मूंगल, अनुली, तोली खर्सू, टकोली, गौना, बड़ूयूड़ा, खिरोली, अनरियाकोट, उज्योला, रतखान-रालाकोट, सत्यों, भैंसोड़ा, ध्युलीरौतेला, लमकोट, रणाऊ, कनरा, बोरा गांव, स्यूनानी, तिवारी जाख, धुरा संग्रोली और बजेठी समेत 28 गांवों के लोग कांग्रेस से जुड़े। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का कांग्रेस में शामिल होना पार्टी की नीतियों और जनहित के मुद्दों पर जनता के बढ़ते विश्वास का संकेत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जनता के बीच सक्रिय रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी क्षेत्रीय मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और जनता के हितों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और संगठन विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख धौलादेवी लीला बिष्ट, प्रदेश सचिव गोपाल बिष्ट, पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र मेर, किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दीवान राम, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नवीन कोहली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जल एवं मच्छर जनित रोगों के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

संवाददाता

देहरादून। स्वास्थ्य विभाग ने जनसामान्य से बासी भोजन का सेवन न करने तथा बाजार में खुले में बिक रहे खाद्य पदार्थों एवं अधपके भोजन से बचने की अपील की है। बरसात में जल जनित एवं मच्छर जनित संक्रामक रोगों की आशंका बढ़ जाती है। डायरिया, पेचिश, टायफायड, हैजा, पीलिया एवं हेपेटाइटिस जैसे जल जनित रोगों के साथ ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों के मामले भी बढ़ने की संभावना रहती है। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (आईडीएसपी) के माध्यम से प्राप्त साप्ताहिक रिपोर्टों के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से विशेष सतर्कता बरतने तथा रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की है। तरबूज, खरबूज, गन्ने का रस आदि का सेवन केवल स्वच्छ एवं सुरक्षित होने पर ही करें। ठंडी वस्तुओं में प्रयुक्त होने वाली बर्फ के सेवन से भी बचें, क्योंकि इसमें दूषित पानी का प्रयोग होने की संभावना रहती है। विभाग ने सलाह दी है कि घर में पानी को अच्छी तरह उबालकर रखें और पीने तथा खाना बनाने में इसी का प्रयोग करें। पानी को क्लोरीनयुक्त करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग स्वास्थ्य कर्मियों के निर्देशानुसार ही किया जाए। शौचालय के उपयोग के बाद तथा भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोने की आदत अपनाएं। फलों एवं सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही सेवन करें। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया से बचाव के लिए लोगों से अपने घरों एवं आसपास पानी एकत्रित न होने देने की अपील की है। सभी पानी की टंकियों एवं जल भंडारण के बर्तनों को ढककर रखें। घरों में लगे गमलों के नीचे पानी एकत्रित करने वाली ट्रे न लगाएं और गमलों में पानी जमा न होने दें। फ्रिज के पीछे, कूलर, गुलदस्तों, मनी प्लांट, पानी के बर्तनों सहित ऐसे सभी स्थानों की नियमित रूप से सफाई करें, जहां पानी जमा हो सकता है। इन वस्तुओं का पानी सप्ताह में कम से कम एक बार पूरी तरह खाली कर उन्हें सुखाकर ही दोबारा उपयोग करें। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से पुराने टूटे बर्तन, बोतल, डिब्बे, बेकार टायर आदि खुले में न फेंकने की अपील की है। इनमें जमा होने वाला पानी डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर के प्रजनन का कारण बन सकता है। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करने, आवश्यकता के अनुसार मच्छररोधी साधनों का उपयोग करने तथा ऐसे कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, जिससे शरीर का अधिक से अधिक हिस्सा ढका रहे। बच्चों एवं आमजन को मच्छर जनित रोगों से बचाव के संबंध में जागरूक करना भी आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि तेज बुखार, सिरदर्द, बदन एवं मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द तथा शरीर पर लाल चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई देने पर इसे नजरअंदाज न करें और तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लें। ये लक्षण डेंगू सहित अन्य संक्रामक रोगों के संकेत हो सकते हैं।

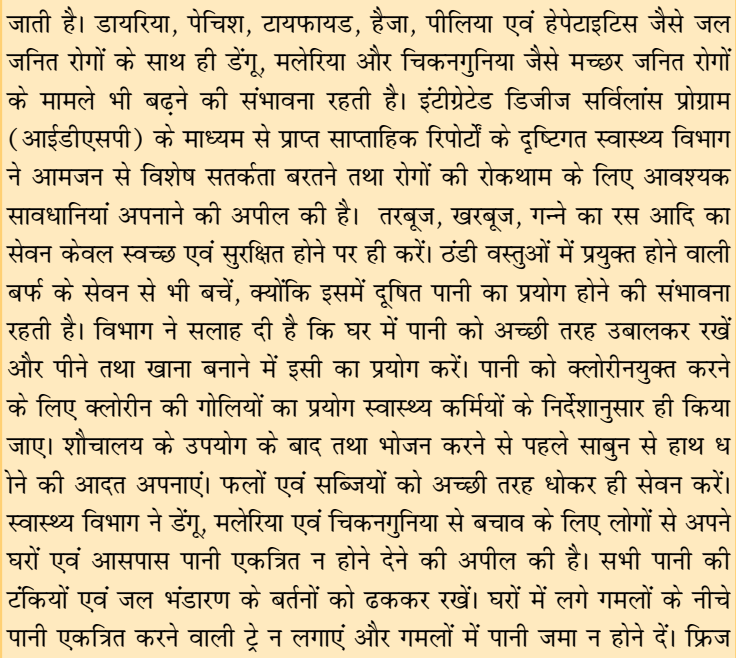

सिख-पंजाबी समाज का धरना जारी

हमारे संवाददाता

देहरादून। गांधी पार्क में सिख और पंजाबी समाज द्वारा आयोजित संयुक्त धरना-प्रदर्शन लगातार जारी है। कुंवर जपेंदर सिंह और पंजाबी महासभा सहित समस्त पंजाबी समाज के नेतृत्व में चल रहे इस अनिश्चितकालीन धरने का मुख्य मुद्दा युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता आकांक्षा नेगी द्वारा विभाजन के समय प्रभावित हुए सिख और पंजाबी परिवारों को 'पाकिस्तानी' बताने वाले कथित बयान पर उनकी गिरफ्तारी की मांग है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब आकांक्षा नेगी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ और पंजाबी समुदाय के सदस्यों को 'पाकिस्तानी' अथार्त बाहरी घोषित कर दिया था। आकांक्षा नेगी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, ने कथित रूप से यह टिप्पणी देहरादून में हुए एक प्रदर्शन के दौरान की थी, जहां कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद थे। जबकि उमेश शर्मा काऊ का परिवार विभाजन विभीषका के बाद से देहरादून में प्रवासित हुआ और अब उत्तराखंड में स्थायी रूप से रह रहा है। वहीं कुंवर जपेंदर सिंह और पंजाबी महासभा सहित समस्त पंजाबी समाज द्वारा प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि आकांक्षा नेगी की टिप्पणी से पंजाबी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और पंजाबी समाज ने देश की एकता, अखंडता और विकास में हमेशा अहम योगदान दिया है। ऐसे में किसी भी समुदाय की पहचान को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करना ठीक नहीं है।

कामकाजी महिलाएं इस प्रकार घर और ऑफिस में तालमेल बैठायें

अधिकांश कामकाजी महिलाओं के लिए घर और ऑफिस से तालमेल बैठाना आसान नहीं होता। इसमें जल्दी में खाना बनाना सबसे कठिन काम होता है। ऑफिस जाने की जल्दी के साथ ही घर में उन्हें सबकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना पढता है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या बनायें और कैसे बनायें।

पकाने की बजाय ग्रिल करें या भून लें

झटपट खाना बनाने के लिए कुछ तरीके अपनाइए। जैसे कुछ रेसिपी जिसमें सब्जियों और जो भी तलने या पकाने में हम जो वक्त बर्बाद करते हैं उससे अच्छा हम उसे भून सकते हैं या ग्रिल कर सकते हैं। इसके अलावा खाने को स्टीम पर पकाना या उसे उबालकर पकाना भी अच्छा विकल्प है। इससे उस खाने के पौष्टिक तत्व भी बरकरार रहते हैं साथ ही खाना बिना झंझट के तुरत पक भी जाता है। गैस पर देर तक पकाने की वजह से पौष्टिक खत्म हो जाते हैं। इस विकल्प को अपनाने से समय तो बचेगा ही, साथ ही आपके गैस की खपत भी कम होगी।

सलाद खाएं

सलाद सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि सलाद को हम पूरा खाना नहीं मानते हैं। पर अगर आप थोढी-सी समझदारी बरतें तो सलाद को नया रूप देकर अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। सलाद में ब्रोकली, शिमला मिर्च, गाजर, खीरा और पत्ता गोभी आदि थोढी कम पकी हों तो भी अच्छी लगती हैं।

आप पहले से ही जब वक्त हो तो इन सब सब्जियों को काटकर फ्रिज में रख लीजिए और जब सलाद बनाना हो, उस समय उन्हें फ्रिज से निकालिए और थोढे-से तेल में सलाद को दो मिनट हल्का तल लीजिए या पका लीजिए। हल्का पकने के बाद इसमें अपनी पसंद के मसाले मिलायें। आप इसमें थोढा-सा लहसुन या सॉस भी डाल सकती हैं। इसे आप रोटी, सब्जी या ब्रेड के साथ खा सकती हैं। यह न सिर्फ झटपट तैयार होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

झटपट करें तैयार, पास्ता-नूडल्स

बच्चे पास्ता और नूडल्स के दीवाने होते हैं, उन्हें पास्ता या नूडल्स पसंद आता है। ये सभी उम्र के बच्चों की पसंद है। अगर आपके बच्चे भी पास्ता या नूडल्स के शौकीन हैं तो आप पास्ता और नूडल्स को उबालकर फ्रिज में 4 से 5 दिनों तक के लिए आराम से स्टोर कर सकती हैं। जब भी बच्चे खाने को मांगे आप स्मार्टली उन्हें उबले हुए पास्ता में सब्जियां, सॉस और थोढा-सा चीज मिलाकर फटाफट तैयार कर खिला सकती है।

सूप है हेल्दी और फटाफट स्टार्टर

पास्ता की ही तरह सूप भी तुरत तैयार किया जा सकता है। और हेल्थ की दृष्टि से भी यह सर्वोत्तम है। इसे जल्दी बनाने के लिए प्रेशर कुकर में अपनी पसंद की सब्जियां डालें और उबालें। अब इन उबली हुई सब्जियों को मिक्सी में पीस लें। जिस पानी में आपने सब्जियां उबाली हैं, उसका कुछ हिस्सा सूप में मिलाएं। यह सूप सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, इसे बनाने में समय भी कम लगता है।

खाने के शॉर्ट कट तरीके अपनाएं

किसी भी खाने को बनाने के लिए आसान प्रक्रिया का चुनाव करें। जैसे, अगर पनीर टिक्का बनाना है तो पनीर को मैरिनेट करने के लिए बाजार में उपलब्ध मैरीनेट को उस पर लगाएं और ओवन में रख दें। पनीर टिक्का आधे से कम समय में तैयार हो जाएगा। पहले से तैयार इन मैरीनेट्स की खासियत होती है कि चाहे पनीर हो या चिकन या मछली, इन्हें लगाने के बाद हमें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पढता। हम इसे तुरंत ही माइक्रोवेव में रखकर अपनी डिश तैयार कर सकते हैं। वहीं घर में मेरिनेट करने के लिए बहुत समय देना पढता है।

कुछ मीठा पहले से बनाकर रख लें

खाना खाने के बाद हर कोई कुछ मीठा खाना पसंद करता है। इसके लिए छुट्टी के दिन ही खीर या हलवा जैसी कुछ चीजें बनाकर रख लें। लेकिन अगर आप कुछ और खाना चाहती हैं तो किसी अच्छी बेकरी से ताजा बनी ब्राउनी या मफिन लाएं और उसे स्टोर करके रख लें।

जब भी उन्हें खाने का मन करे, उसे निकालें और माइक्रोवेव में एक मिनट के लिए गर्म करें। उस पर चॉकलेट सॉस या फिर आइसक्रीम डालें। आपके लिए बेहद लजीज डेजर्ट झट से तैयार है। इसके अलावा कस्टर्ड भी काफी जल्दी बनने वाली डिश है और इसे भी आप पहले से बनाकर रख सकती हैं।

सब्जी बनाने समय मसाले को बनाने में ज्यादा समय लगता है। प्याज काटो. भूनो फिर टमाटर को काटकर डालो। इन सबमें काफी वक्त जाया होता है। इससे अच्छा है कि प्याज लहसन अदरक सब पीसकर भून ले। भुन जाने के बाद इन्हें एयर टाईट डिब्बे में भरकर रख लें। अब सब्जी काटें, बस कढाही में डालें, मसाले का पेस्ट निकालें, मसाला मिलाकर थोढी देर भून लें अब आपकी सब्जी झटपट है तैयार। तो बस...इन तरीकों को अपनाकर हो जाइए आप भी स्मार्ट। इस प्रकार आपका काम भी समय पर हो जाएगा और आपको अपने लिए समय भी मिल जाएगा।

शब्द सामर्थ्य -063

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं :

1. अनुचित, असत्य, जो ठीक न हो 3. बेवजह, बिनाकारण, व्यर्थ 4. हल्कीनींद, चकमा, धोखा 6. शक्कर पानी आदि का मीठा घोल 10. सोते से उठाना, सावधान करना, प्रदीप्त करना 11. चरमसीमा, सीमांत 14. पानी, आंसू 15. बैठा हुआ, विराजित 16. नृत्य 17. मृतप्राय, मृत्यु के करीब 19. जल, अम्बु 22. उपहार, भेंट 23. खबर, संदेश।

ऊपर से नीचे

1. गणपतिजी, 2. मांगनेवाला, पाने की इच्छा करने वाला 3. मिट्टी के रंग का, मटमैला 5. चला आता हुआ क्रम प्रथा, प्रणाली, रीति-रीवाज, 7. निशाचर, रात में विचरण करने वाला 8. पेड़ का धड़ा जहां से शाखाएं निकलती है, 9. मिठाई, खाने की मीठी चीज 12. शासन, गुप्तबात 13. श्रद्धा, स्त्री, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य 15. विपत्तिग्रस्त, दुखी, अभागा 16. प्रसिद्ध, नामवर 18. स्वप्न, ख्वाब 20. करीब, नज़दीक, समीप 21. सुबह, प्रातः, सबेरा।

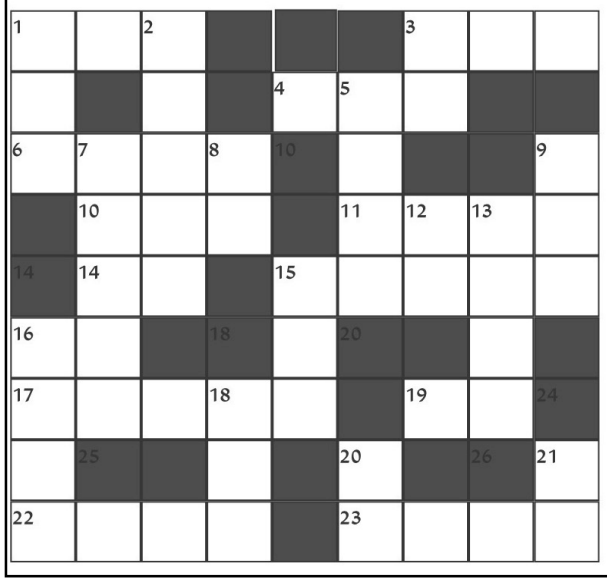

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 62 का हल

अ	भि	षे	क	■	प	स	■	■
जा	त	■	थ	प	थ	पा	ना	■
य	र	का	नी	■	भ्र	■	र	श्मि
ब	घा	र	■	क	ष्ट	प्र	द	■
■	त	ना	त	नी	■	र्व	■	ब
अ	■	मा	■	ज	मा	त	■	ल
स	जा	■	■	■	■	क	ज	रा
बा	■	बे	स	हा	रा	■	ग	म
ब	गु	ला	■	रा	ज	दू	त	■

मोहनलाल अब ऑपरेशन गंगा से मचाएंगे धूम, जबरदस्त है पहली झलक

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल के बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट एल367' के आधिकारिक नाम की घोषणा कर दी गई है। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए फिल्म का नाम ऑपरेशन गंगा' घोषित किया। विष्णु मोहन के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को लेकर मोहनलाल के प्रशंसकों में पहले से ही काफी उत्सुकता थी। फिल्म का निर्माण श्री गोकुलम मूवीज के बैनर तले गोकुलम गोपालन कर रहे हैं। आधिकारिक नाम की घोषणा के साथ यह भी स्पष्ट हो गया है कि फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है, जिसमें मलयालम सिनेमा के साथ हिंदी सिनेमा और अंतरराष्ट्रीय स्तर के तकनीकी विशेषज्ञों की प्रतिभा को शामिल किया गया है। फिल्म का नाम भारत सरकार द्वारा चलाए गए एक बड़े बचाव अभियान ऑपरेशन गंगा' पर आधारित है। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक, विशेष रूप से छात्र, यूक्रेन में फंस गए थे। उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाया था।

फिल्म इसी महत्वपूर्ण अभियान से प्रेरित कहानी के जरिए दर्शकों को उस समय की परिस्थितियों और भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के प्रयासों से रूबरू कराएगी। निर्माताओं के अनुसार, फिल्म में इस बड़े अभियान को प्रभावशाली और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।

ऑपरेशन गंगा' का निर्देशन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्मकार विष्णु मोहन कर रहे हैं। वह मलयालम फिल्म उद्योग से जुड़े हैं और राजनीतिक नाटक पर आधारित फिल्म मेप्पडियान' के निर्देशन के लिए पहचाने जाते हैं। वर्ष 2022 में इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। फिल्म का निर्माण गोकुलम गोपालन कर रहे हैं। बैजू गोपालन और वी. सी. प्रवीण सह-निर्माता हैं, जबकि कृष्णमूर्ति कार्यकारी निर्माता की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। फिल्म में मोहनलाल के साथ हिंदी सिनेमा के अभिनेता अर्जुन रामपाल, आदिल हुसैन और भाग्यश्री भोरसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। अभिनेता पार्थिबन भी फिल्म के कलाकारों का हिस्सा हैं।

फिल्म की तकनीकी टीम भी काफी खास है। पुष्पा' और पुष्पा 2' के लिए चर्चित छायाकार मिरोस्लाव कुबा ब्रोजेक फिल्म की छायांकन जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। संगीत शाश्वत सचदेव तैयार कर रहे हैं, जबकि चर्चित कार्रवाई निर्देशक सी यंग ओह फिल्म के रोमांचक दृश्यों को आकार देंगे। ऑपरेशन गंगा' की आधिकारिक घोषणा के बाद मोहनलाल के प्रशंसकों के साथ-साथ भारतीय सिनेमा के दर्शकों की नजर अब फिल्म की अगली जानकारी और प्रदर्शन तिथि पर टिकी है।

सूर्या की विश्वनाथ एंड सन्स' नेटफ्लिक्स पर आने की चर्चा

अभिनेता सूर्या और निर्देशक वेंकी अटुलुरी की फिल्म %विश्वनाथ एंड सन्स' सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब ओटीटी मंच पर दस्तक देने की तैयारी में है। ममिता बैजू के साथ मुख्य भूमिका वाली यह तमिल-तेलुगु पारिवारिक फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन करते हुए सूर्या के करियर की प्रमुख व्यावसायिक सफल फिल्मों में अपनी जगह बनाई है। सितारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यून फोर सिनेमाज के बैनर तले सूर्यदेवरा नागा वामसी और साई सौजन्या ने फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म अभी भी कुछ सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है। इसी बीच फिल्म उद्योग में चर्चा है कि सिनेमाघरों में रिलीज के करीब एक महीने बाद 11 सितंबर को फिल्म को नेटफ्लिक्स पर कई भाषाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है। हालांकि, इस संभावित ओटीटी रिलीज तारीख की अभी नेटफ्लिक्स की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिल्म से जुड़े व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार, %विश्वनाथ एंड सन्स' ने तीसरे सप्ताह तक दुनिया भर में 25० करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। भारत में भी फिल्म का शुद्ध कारोबार तीसरे सप्ताह तक 15० करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया था। तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में फिल्म को दर्शकों का अच्छा समर्थन मिला है।

भाषा के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 14 दिनों में भारत में फिल्म के तमिल संस्करण ने करीब 77.48 करोड़ रुपये, जबकि तेलुगु संस्करण ने लगभग 72.7० करोड़ रुपये का शुद्ध कारोबार किया। इस तरह दोनों भाषाओं से फिल्म का कुल शुद्ध कारोबार करीब 15० करोड़ रुपये रहा। इन आंकड़ों को फिल्म की सफल द्विभाषी सिनेमाघरी यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है।

%विश्वनाथ एंड सन्स' की कहानी संजय विश्वनाथ के इर्द-गिर्द घूमती है। शादी को लेकर हिचकिचाहट के बावजूद संजय किराये की कोख के माध्यम से पिता बनते हैं। बाद में जब उनके बच्चे को अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है, तब बच्चे की जैविक मां मैडी उनकी जिंदगी में प्रवेश करती हैं। मैडी के आने के बाद दोनों के बीच भावनात्मक रिश्ता विकसित होता है, लेकिन उम्र का अंतर उनके संबंधों को जटिल बना देता है। फिल्म में पारिवारिक भावनाओं के साथ प्रेम, रिश्तों की उलझन और व्यक्तिगत संघर्ष को कहानी का आधार बनाया गया है। फिल्म में सूर्या और ममिता बैजू की जोड़ी को दर्शकों का विशेष ध्यान मिला है। दोनों कलाकारों के बीच की भावनात्मक केमिस्ट्री फिल्म की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक भावनाओं और रिश्तों पर आधारित इस फिल्म ने तमिल और तेलुगु दोनों क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। अब दर्शकों को फिल्म के ओटीटी प्रदर्शन का इंतजार है। 11 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर इसके संभावित प्रदर्शन की चर्चा जरूर है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए नेटफ्लिक्स की घोषणा का इंतजार करना होगा।

पूजा हेगड़े का रेड हॉट अवतार हुआ वायरल, इंडो-वेस्टर्न लुक में दिखीं बेहद ग्लैमरस

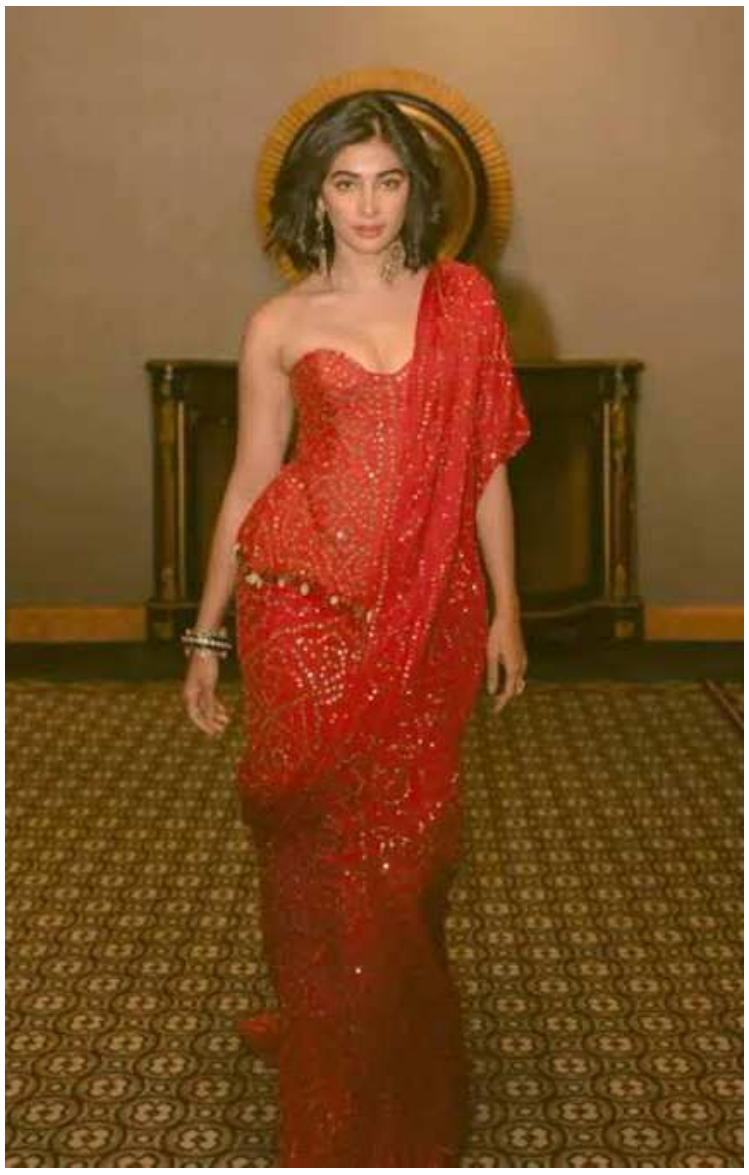

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की गॉर्जियस एक्ट्रेस पूजा हेगड़े एक बार फिर अपने फैशनेबल और ग्लैमरस अवतार को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका लुक देखते ही बन रहा है।

तस्वीरों में पूजा हेगड़े ब्राइट रेड कलर का बेहद अट्रैक्टिव इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन एंसेंबल पहने नजर आ रही हैं। उनकी यह ड्रेस एक प्री-ड्रैप्ड साड़ी और पेपलम स्टाइल कांबिनेशन का बेहतरीन मेल है। आउटफिट पर बारीक मिरर वर्क, सेक्विन और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है।

ट्रेडिशनल टच के साथ-साथ इसमें एक मॉडर्न ट्विस्ट भी दिया गया है। स्ट्रैपलेस कॉर्सेट-स्टाइल ब्लाउज और बैक पर बनी क्रॉस-डिटेलिंग पूजा हेगड़े के पूरे लुक को बोल्ड और एलिगेंट बना रही है।

अपने इस गॉर्जियस रेड आउटफिट को कम्प्लीट करने के लिए पूजा ने ज्वेलरी को बेहद मिनिमल रखा है। उन्होंने हैवी गोल्ड और स्टोन-स्टडेड डैंगलर इयररिंग्स चुने हैं, जो उनके एथनिक टच को और बढ़ा रहे हैं।

हेयर स्टाइलिंग की बात करें तो, उन्होंने अपने शॉर्ट हेयर को सॉफ्ट वेव्स के साथ ओपन रखा है। वहीं, न्यूड लिपकलर, सॉफ्ट स्मोकी आइज और हाइलाइटेड चीकबोन्स के साथ उनका सटल मेकअप उनके फेशियल एक्सप्रेशन को और उभार रहा है।

रॉयल बैकड्रॉप और क्लासिक इंटीरियर के बीच खिंचवाई गई इन तस्वीरों में पूजा के बोल्ड और ग्रेसफुल पोज फैंस का ध्यान खींच रहे हैं। कभी सीढ़ियों के पास तो कभी विंटेज डोर के सहारे पोज देते हुए पूजा का कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन पूरी तरह से ऑन-पॉइंट नजर आ रहा है।

हुंकार-द रोर का दमदार टीजर जारी, सैयारा के बाद अनीत पड्डा ने दिखाया नया अवतार

सैयारा की वाणी यानी अनीत पड्डा अब एक नए और बिलकुल अलग अवतार में नजर आने वाली हैं। अनीत नई ड्रामा सीरीज हुंकार-द रोर में नजर आने वाली हैं, जिसका टीजर जारी किया जा चुका है। यह सीरीज एक ऐसे आरोप के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक ताकतवर सिस्टम को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। कहानी 17 साल की मीनू रावत के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार अनीत पड्डा निभा रही हैं। मीनू बापजी के नाम से मशहूर जाने-माने कल्ट लीडर सुनील चाकोसी पर एक आरोप लगाती है, जिसके बाद बापजी के खिलाफ बड़ी जांच शुरू हो जाती है। टीजर से साफ है कि एक आरोप से शुरू होने वाली कहानी जल्दी ही एक बड़ी लड़ाई में बदल जाती है और मामला पुलिस के बाद कोर्ट और मीडिया तक पहुंचता है और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है।

हुंकार के टीजर में तीन मुख्य किरदार देखने को मिलती हैं और तीनों किरदार एक ही लड़ाई को अलग-अलग तरीके से लड़ रहे हैं। एसीपी जसलीन सिंह सोनी पुलिस की तरफ से यह केस की कमान संभालती हैं। भलेराव एक स्ट्रगलिंग वकील हैं जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, जबकि पत्रकार अमिताभ मीडिया के जरिए इस कहानी को कवर करते हैं। इस सीरीज में पुलिस की जांच से लेकर कोर्टरूम ड्रामा और मीडिया ट्रायल तक सब देखने को मिलेगा और जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ता है, राष्ट्रीय स्तर पर ये केस चर्चा का विषय बन जाता है।

इंस्टाग्राम पर टीजर शेयर करते हुए, अनीत पड्डा ने अपने फैंस को इस सीरीज के बारे में जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि इसकी शूटिंग सैयारा से पहले ही हो गई थी। टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में अनीत ने लिखा- पेश है एक छोटी सी चीज जिसकी शूटिंग मैंने सैयारा से पहले की थी। हुंकार कुछ समय से मेरे सफर का हिस्सा रही है, और मुझे खुशी है कि आखिरकार मैं इसे आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं। अब इंसाफ का इंतजार नहीं होगा, बस सच्चाई की हुंकार गूंजेगी। हॉटस्टार स्पेशल्स हुंकार - द रोर, 25 सितंबर से सिर्फ जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। हुंकार्स द रोर का निर्देशन करण डी कपाड़िया, नित्या मेहरा और हीराज मरफातिया ने किया है। इस सीरीज में अनीत पड्डा के साथ फ़ातिमा शेख, अर्जुन माथुर, मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब, रघुबीर यादव और राम कपूर जैसे कलाकार शामिल हैं। हुंकार्स द रोर का प्रीमियर 25 सितंबर को जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। अनीत पड्डा की बात करें तो वह शक्ति शालिनी में भी नजर आएंगी, जिसके सेट से पिछले दिनों अनीत के वीडियोज भी सामने आए थे। इन वीडियोज में अनीत स्कूल गर्ल वाले लुक में दिखाई दी थीं।

जिलाधिकारी ने जीआईसी लोधिया का किया निरीक्षण, जर्जर भवन ध्वस्त कर नए भवन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश

अल्मोड़ा(आरएनएस)। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने राजकीय इंटर कॉलेज लोधिया का स्थलीय निरीक्षण कर विद्यालय भवनों की स्थिति और शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जर्जर भवनों को नियमानुसार ध्वस्त कर नए विद्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विद्यालय के विभिन्न कक्षा-कक्षों एवं भवनों का निरीक्षण करते हुए उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए जर्जर भवनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई में विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि निर्धारित प्रक्रिया और तकनीकी मानकों के अनुरूप जर्जर भवनों को ध्वस्त करने की कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही नए विद्यालय भवन के निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाए, ताकि आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर में आपदा मद के अंतर्गत कराए जा सकने वाले कार्यों का आकलन कर प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवनों से संबंधित आवश्यक कार्य समयबद्ध ढंग से कराए जाएं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और विद्यालय में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

राइस मिलरों ने धान खरीद में जतायी असमर्थता

रुद्रपुर(आरएनएस)। छह साल से 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान लंबित होने से राइस मिलर्स भड़क गए हैं। नाराज राइस संचालकों ने तहसील में प्रदर्शन कर चार सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम को सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो इस बार वे कच्चे आढ़तियों से धान की खरीद नहीं करेंगे।उत्तराखंड राइस मिलर्स एसोसिएशन खटीमा के अध्यक्ष ईश्वर बंसल के नेतृत्व में राइस मिल संचालकों ने एसडीएम तुषार सैनी को बताया कि वर्ष 2019 से 2025 तक राइस मिलर्स का 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान लंबित है। उन्होंने वर्ष 2025-26 के चावल का उतार कराने और उसके भुगतान की समयसीमा स्पष्ट करने की मांग की। मिलर्स ने सरकार से मंडी शुल्क का भुगतान करने के साथ ही पिछले वर्ष राइस मिल संचालकों से लिया गया 0.5 प्रतिशत विकास सेस वापस करने की मांग की। उन्होंने कस्टम मिलिंग चार्ज का पुनर्निर्धारण करने और प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 80 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग भी उठाई। राइस मिलर्स ने कहा कि लंबे समय से भुगतान लंबित होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों का समाधान नहीं होने पर वे कच्चे आढ़तियों के माध्यम से धान की खरीद नहीं करेंगे। ज्ञापन देने वालों में महामंत्री संजय अग्रवाल, वरुण अग्रवाल, संजय गोयल, रिदम अग्रवाल, हरप्रीत सिंह महल, श्याम सुंदर, योगेश गर्ग, अनिल अग्रवाल, सुनील बत्रा, राजू अग्रवाल, विक्की और सुधांशु अग्रवाल आदि शामिल रहे।

सू- दोकू क्र.063

	6	3		8		1		4
8			3		4		7	
	4			5		8		
3		8			1		4	
	1			4		9		7
		4			2		1	
1				3		4		8
	8		2		9		3	
		9		1		2		5

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र. 62 का हल

6	7	9	2	4	5	3	1	8
2	1	8	3	7	6	9	5	4
7	6	4	5	2	8	1	3	9
3	8	1	6	9	7	2	4	5
9	2	5	4	1	3	8	6	7
8	3	7	9	6	4	5	2	1
5	4	2	8	3	1	7	9	6
1	9	6	7	5	2	4	8	3
4	5	3	1	8	9	6	7	2

निर्माण कार्यों में अब किसी भी स्तर पर हीलाहवाली नहीं चलेगी : मेलाधिकारी

हरिद्वार(आरएनएस)। कुंभ मेला-2027 के कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के लिए मेला प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया है। मेलाधिकारी सोनिका ने कुंभ क्षेत्र में शामिल सभी जिलों के करीब डेढ़ दर्जन जिला स्तरीय अधिकारियों एवं उप जिलाधिकारियों को भी विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कुंभ मेला कार्यों के अनुश्रवण की जिम्मेदारी सौंपी है। नामित अधिकारी नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर प्रत्येक सप्ताह कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता से संबंधित रिपोर्ट मेलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।

मेलाधिकारी सोनिका ने नामित अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की निरंतर निगरानी करें। किसी योजना के क्रियान्वयन में समस्या सामने आने पर उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित कराया जाए। ऐसे प्रकरण, जिनमें उच्चाधिकारियों के स्तर से हस्तक्षेप अथवा आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता हो, उन्हें बिना विलंब संज्ञान में लाया जाए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुंभ मेला के कार्यों में अब किसी भी स्तर पर हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण स्थलों पर पूरी क्षमता के साथ कार्य होना चाहिए और कार्यों की गति के साथ गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल समाप्त होने के बाद प्रारंभ होने वाले निर्माण कार्यों की अभी से पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही, गंगनहर के क्लोजर के दौरान प्रस्तावित घाटों के निर्माण एवं मरम्मत से संबंधित कार्यों के लिए संबंधित विभाग आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर लें।

मेलाधिकारी ने विशेष रूप से फुटपाथ, सड़कों एवं चौराहों के निर्माण तथा सुधार कार्यों को लेकर स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर से प्राप्त उपयोगी एवं व्यावहारिक सुझावों को कार्ययोजना में शामिल किया जाए, ताकि निर्माण कार्य जनसुविधाओं के अनुरूप अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बन सकें।

आगामी कुंभ मेला को लेकर कुंभ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति के कार्य संचालित हैं तथा अनेक अस्थायी कार्य शीघ्र प्रारंभ होने वाले हैं। मेला प्रारंभ होने से पहले सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे कराने के लिए मेला प्रशासन ने संबंधित विभागों को पूरी क्षमता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की विभिन्न स्तरों पर निगरानी की व्यवस्था की गई है।

कुंभ क्षेत्र में हरिद्वार के साथ ही देहरादून, पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी गढ़वाल जिलों के क्षेत्र शामिल हैं। संपूर्ण कुंभ क्षेत्र को 32 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इन्हीं सेक्टरों में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं उप जिलाधिकारियों को कुंभ मेला कार्यों के अनुश्रवण की जिम्मेदारी दी गई है।

मेलाधिकारी सोनिका ने नामित अधिकारियों को घाटों, पुलों सहित अन्य बड़ी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरे होना आवश्यक है। इसके लिए नियमित स्थलीय निरीक्षण करते हुए कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं मौके पर उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा की जाए।उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी विभिन्न निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लेंगी। नामित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर प्रत्येक सप्ताह की रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। मेला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी अपने-अपने स्तर से निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। बड़ी परियोजनाओं तथा जिन कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, वहां संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मेलाधिकारी ने विभिन्न सेक्टरों में प्रस्तावित शिविर स्थलों के लिए भूमि की ड्रेसिंग एवं लेवलिंग का कार्य भी तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने नामित अधिकारियों को आगामी स्थलीय निरीक्षण के दौरान इन कार्यों की प्रगति एवं वस्तुस्थिति का भी जायजा लेने को कहा। साथ ही, कुंभ मेला योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे सौंदर्यीकरण एवं पौधारोपण कार्यों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मेलाधिकारी ने कहा कि कुंभ मेला-2027 के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए प्रत्येक कार्य का समय पर पूरा होना आवश्यक है। इसके लिए निरंतर निगरानी, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और मौके पर त्वरित निर्णय की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है।

बैठक में नगर आयुक्त नंदन कुमार, अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता, सचिव एचआरडीए प्रत्यूष कुमार, नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार हरि गिरी, उप मेलाधिकारी मनजीत सिंह, एसडीएम हरिद्वार यागेश मेहरा, एसडीएम ऋषिकेश (देहरादून) कुमकुम जोशी, एसडीएम यमकेश्वर (पौड़ी गढ़वाल) चतर सिंह चौहान, एसडीएम रुड़की देवेंद्र नेगी, जिला पंचायत राज अधिकारी एमएम खान, उप प्रभागीय वनाधिकारी पूनम कैंथोला, जिला विकास अधिकारी के.के. पंत, मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अभियंता से मारपीट के विरोध में इंजीनियरों का अल्टीमेटम

बागेश्वर(आरएनएस)। बाजपुर के लेवड़ा पुल पर बरसात का पानी आने के मामले में लोक निर्माण विभाग के अपर सहायक अभियंता राजीव गौड़ से मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप पूर्व विधायक प्रत्याशी राजेश कुमार और उनके साथियों पर लगा है। घटना के विरोध में बागेश्वर निरीक्षण भवन में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ की आपात बैठक हुई। अभियंताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संघ के अनुसार, पीड़ित अभियंता ने बाजपुर कोतवाली में तहरीर दी है। संघ ने प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो जिलेभर में विकास कार्य बंद कर इंजीनियर कार्य बहिष्कार करेंगे।इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विपिन चंद्र सनवाल और संचालन महिला उपाध्यक्ष दीपिका ने किया। इस दौरान पूनम बिष्ट, गौरव पांडे, नेहा सिंह, विकास सिंह, शैलेश और दिव्या समेत कई अभियंता मौजूद रहे।

जनता दरबार में 15 फरियादी पहुंचे शिकायत लेकर

बागेश्वर (आरएनएस)। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत कलक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया। सड़क, पेयजल, पेंशन, मुआवजा समेत विभिन्न मामलों को लेकर 15 लोग शिकायतें लेकर पहुंचे। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वांसतोली क्षेत्र में खनन से खेतों को हुए नुकसान की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी एनएस नबियाल ने जिला खान अधिकारी को मौके पर स्थलीय निरीक्षण कर जांच करने और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

मनीगांव-कांडे में पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त करने की शिकायत पर जल संस्थान के अधिकारियों को संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया। अमतोड़ा-डुंगरगांव सड़क निर्माण से प्रभावित काश्तकारों को नियमानुसार मुआवजा दिलाने के लिए लोनिवि के अधिशासी अभियंता को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और 'हेलो बागेश्वर' पोर्टल पर लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने 36 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतकर्ताओं से स्वयं वार्ता कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वैप्कॉस के जेई को नोटिस- जनता दरबार में वैप्कॉस के जेई अनुपस्थित रहे। इस पर एडीएम ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना। सीडीओ को अनुपस्थित जेई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

हिमालय दिवस पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

विषयः पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण-वैज्ञानिक दृष्टिकोण

हमारे संवाददाता

देहरादून। हिमालय दिवस के अवसर पर आज भाकृअनुप – भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून द्वारा कृषि प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान देहरादून के संयुक्त सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का मुख्य विषय उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण-वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा। कार्यशाला का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते भू-क्षरण, जल संकट और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर वैज्ञानिक चर्चा करना और किसानों एवं छात्रों को कम लागत की संरक्षण तकनीकों से अवगत कराना था। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में मैती आंदोलन के प्रणेता पद्मश्री श्री कल्याण सिंह रावत उपस्थित रहे। वहीं कार्यशाला की अध्यक्षता डॉ. चरण सिंह ने की। कार्यशाला के संयोजक संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. जे. एम.एस. तोमर रहे, जबकि कार्यशाला का संचालन डॉ. विभा सिंघल एवं डॉ. जय प्रकाश द्वारा किया गया। कार्यशाला के मुख्य बिन्दुओं में मुख्य अतिथि कल्याण सिंह रावत ने अपने संबोधन में हिमालय के बुग्यालों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बुग्याल हिमालय की आत्मा हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में जल का मुख्य स्रोत भी हैं। यदि समय रहते इनका वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण नहीं किया गया तो यह हिमालय के लिए एक बड़ी क्षति होगी। निदेशक डॉ. चरण सिंह ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में बताया कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल अधिक होने के कारण मृदा का कटाव एक गंभीर समस्या है। जल संचय टांके, जैविक पुश्ता और वानस्पतिक अवरोध जैसी कई कम लागत की वैज्ञानिक तकनीकें विकसित की हैं, जिनसे मृदा एवं जल दोनों का संरक्षण किया जा सकता है।

व्हटसएप पर गाली गलौच करने पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा

संवाददाता

देहरादून। व्हटसएप पर गाली गलौच करने के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करा दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेन्द्र नगर निवासी निखिल सिंह ने कैण्ट कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसके फोन पर अज्ञात नम्बर से फोन आया और फोन करने वाले ने उसके साथ व्हटसएप पर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

शराब के साथ गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने शराब के साथ एक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने श्यामपुर लोहे के पुल के पास एक एक्टिवा सवार को रूकने का इशारा किया तो वह पुलिस को देखकर भाग खडा हुआ। पुलिस ने पीछा कर उसको थोडी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 45 पव्वे शराब के बरामद कर लिये। पूछताछ में उसने अपना नाम संजीव सिंह पुत्र बुद्ध सैन निवासी स्वर्गआश्रम लक्ष्मण झूला बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

घर के बाहर से एक्टिवा चोरी

संवाददाता

देहरादून। चोरों ने घर के बाहर से एक्टिवा चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार चन्द्रबनी निवासी अभिनाथ चौधरी ने पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसने अपनी एक्टिवा घर के बाहर खडी की थी। लेकिन जब वह थोडी देर बाद बाहर आया तो उसकी एक्टिवा अपने स्थान से गायब थी। पुलिस ने मुंकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

लाल तप्पड़ क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन

संवाददाता

ददेहरादून। लाल तप्पड में टूटे पुल के निर्माण के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया।

आज लाल तप्पड माजरी में टुटे हुए पुल के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाल तप्पड़ माजरी हाईवे के किनारे धरना प्रदर्शन किया, प्रदर्शन संयोजक और पूर्व राज्य मंत्री व कांग्रेस नेता मनीष कुमार नागपाल ने कहा कि आज लगभग डेढ़ साल हो चुका है और यह पुल टूटा हुआ है जिस पुल के ऊपर से लगभग रोज लाखों गाड़ियां जाती आती हैं उस पुल का निर्माण आज तक भाजपा की ट्रिपल इंजन और डबल इंजन सरकार नहीं कर पाई यह बहुत ही शर्म और दुख की बात है कि सरकार की कानों में जून नहीं रेंग रही है जबकि विधानसभा से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर यह पुल टूटा हुआ है सरकार लगातार विकास कार्यों का बखान करती रहती है जो एकदम झूठ मनगढ़ंत है इस सरकार के कार्यकाल में एक पुल सही नहीं हो रहा है तो और क्या करेंगे यह हाल जबकि यहां से सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब भाजपा के हैं तब यह हाल है स्कूल की टूटने की वजह से आए दिन यहां पर एक्सीडेंट होते रहते हैं क्योंकि सिंगल ट्रैक है सिंगल ट्रैक पर दोनों तरफ गाड़ियां चलती हैं जिसके कारण रोज दुर्घटनाएं होती रहती है कई लोग इस पुल के कारण मौत की आगोश में समा गए हैं अब तक एक्सीडेंट में इस स्कूल के टूटने के कारण जो नदी में अपना रुख अपनाया है उसे रूप के कारण किसानों के खेत बह गए किसानों के खेतों को खतरा है ना नदी के किनारे कोई रिटेनिंग दिवार बनाई गई है जिससे हजारों की संख्या में जनता रहती है ऊपर से बाढ़ आदि का खतरा हर समय मंडराता रहता है जबकि यह एक औद्योगिक क्षेत्र है यहां पर सैकड़ो उद्योग की इकाइयां लगी हुई है उसके बावजूद गूंगी बहरी बनी हुई है और आज तक पुल का इन्होंने निर्माण नहीं किया है केवल झूठी घोषणाएं और मनगढ़ंत बातें करके आज तक यह लोग जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। भाजपा के विधायक जिन्होंने इस क्षेत्र का बेड़ा गर्ग करके रख दिया है उनको भी शर्म आनी चाहिए, इनकी इनकी ही उदासीनता के कारण आज तक इस पुल का निर्माण नहीं हो सका है यह केवल जनता को गुमराह करके यहां से चुनाव जीते और आने वाले समय में जनता इनको इनके नकारेपन के लिए उनकी उदासीनता के लिए और क्षेत्र का बेड़ा गर्ग करने के लिए सबक सिखाएगी।

धरना प्रदर्शन को मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र बर्तवाल, सुनील थपलियाल शंकर सिंह मेहरारू,वचन राम, शेर सिंह, ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदीप पाल, शेर सिंह सक्सेना, किशन शर्मा, गुलाब भगत, चौधरी बलदेव सिंह, राणा पप्पू, ठेकेदार अश्वनी चौधरी, अशोक, मुकेश सक्सेना कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पुलिस ने बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण का दिया संदेश

संवाददात

टिहरी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद टिहरी गढ़वाल, श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन में कोतवाली नरेंद्रनगर, थाना हिंडोलाखाल, कोतवाली कीर्तिनगर, कोतवाली देवप्रयाग, कोतवाली घनसाली, कोतवाली मुनिकीरेती, कोतवाली केंपटी एवं जनपद के अन्य थानों की पुलिस द्वारा जनपद के स्कूलों में पहुंचकर छात्र-छात्राओं से संवाद करते हुए टीम गौरा के माध्यम से महिला सशक्तीकरण एवं बालिका सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्राओं को महिला एवं बालिका सुरक्षा, आत्मरक्षा एवं उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही छात्र-छात्राओं को साइबर फ्रॉड से बचाव एवं नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया।

राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु समिति की बैठक आयोजित

संवाददाता

टिहरी। राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। आज यहां जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य आंदोलनकारी के रूप में चिन्हीकरण हेतु प्राप्त कुल 28 आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया। समिति द्वारा परीक्षण के उपरांत दो आवेदन पत्रों को सर्वसम्मति से राज्य आंदोलनकारी के रूप में चिन्हीकरण हेतु चयनित किया गया। वहीं 18 आवेदन पत्रों को आवश्यक अभिलेखों/जानकारी के आधार पर आगामी बैठक में पुनर्विचार हेतु रखने का निर्णय लिया गया तथा 08 आवेदन पत्रों को शासनादेश में निर्धारित पात्रता मानकों के अनुरूप न पाए जाने के कारण निरस्त किया गया। समिति द्वारा सर्वसम्मति से चयनित आवेदकों में ओम प्रकाश भट्ट निवासी विधि विहार, नई टिहरी तथा स्वर्गीय तोता सिंह ग्राम कुमाली, पट्टी कुजणी टिहरी गढ़वाल शामिल हैं। वहीं जगत सिंह, जौनपुर, तहसील धनौल्टी, वीरेंद्र सिंह, जौनपुर, तहसील धनौल्टी तथा उस्मान, नई टिहरी आदि के आवेदन शासनादेश के अनुसार निर्धारित पात्रता न पाए जाने के कारण समिति द्वारा निरस्त किए गए। समिति द्वारा सुंदरमणि, ग्राम बडोन, तहसील कीर्तिनगर, विक्रम सिंह बिष्ट, नई टिहरी तथा विद्या नेगी, बौराड़ी, नई टिहरी सहित अन्य लंबित प्रकरणों को आगामी बैठक में पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

श्री कृष्ण की छठी पर्व पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने किया प्रसाद वितरण

संवाददाता

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपने हाथों से श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया।

आज यहां भगवान श्री कृष्ण की छठी पर्व पर नैशविला रोड में वर्षों से युवा सेवा दल द्वारा परंपरागत लगने वाले भंडारे में हजारों लोगों ने भगवान का प्रसाद प्राप्त किया और जय श्री कृष्णा का उद्घोष किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपने हाथों से श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया और जन समुदाय को छठी पर्व की बधाई देते हुए कहा कि द्वापर युग अवतरित हुए भगवान कृष्ण ने

स्वयं गीता के उपदेश में उद्घोष किया कि ष्हे अर्जुन मैं नारायण हूँ और जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, सदियों व सज्जनों पर अत्याचार होता है तब तब मैं स्वयं ध रती पर अवतरित होता हूं और दुष्टों का नाश और साधु सज्जनों का कल्याण करता हूं और धरती से पाप नाश करता हूं, यह युगों युगों से यह चल रहा है। ष श्री धस्माना ने कहा कि मनुष्य रूप में जन्माष्टमी के दिन अवतरित हुए भगवान कृष्ण की आज पूरे देश में और दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले छठी मना रहे हैं। श्री धस्माना ने सभी कृष्ण भक्तों को छठी पर्व की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर संजय कुमार कन्नौजिया कद्दू दिनेश कौशल, अमीचंद सोनकर, आनंद सिंह पुंडीर, सुशील डोभाल, विनीत नागपाल, प्रकाश चंद, किशोर गेरा, राज रावत, ऋषभ माटा , कार्तिक बंसल, राहुल माटा, मोहन काला, प्रकाश नेगी आदि उपस्थित रहे।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मिलेगी नई गति : डॉ. धकाते

संवाददाता

देहरादून। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने बताया कि 01 अप्रैल 2026 से देशभर में लागू इस नियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उत्तराखंड में शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। नए नियमों में कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ-साथ सर्कुलर इकोनॉमी, स्रोत पर कचरा पृथक्करण, रिसाइक्लिंग एवं संसाधनों के पुनः उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है।

इस मौके पर सहायक निदेशक पीआईबी देहरादून से संजीव सुन्दियाल एवं निदेशक शहरी विकास प्रवीण कुमार भी मौजूद रहें। डॉ. धकाते ने बताया कि वर्ष 2016 के नियमों में कचरा पृथक्करण की तीन श्रेणियां निर्धारित थीं, वहीं नए नियमों में चार श्रेणियों यथा गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल वाला कचरा में कचरा पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। वहीं 2,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल, प्रतिदिन 40 हजार लीटर से अधिक जल खपत अथवा प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों

में से किसी एक मानक को पूरा करने वाले प्रतिष्ठान बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आएंगे। ऐसे संस्थानों का पंजीकरण तथा कचरे के प्रसंस्करण और रिसाइक्लिंग की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 फरवरी 2026 को Bhopal Municipal Corporation बनाम डॉ. सुभाष चंद्र पांडे मामले में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जनपद में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल सेल गठित किए गए हैं। इन सेल के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, डंपिंग साइट और लीगेसी वेस्ट के निस्तारण की लगातार निगरानी की जा रही है। लीगेसी वेस्ट के निस्तारण को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में राज्य में लगभग शत प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण किया जा रहा है। चार श्रेणियों में कचरा पृथक्करण को ध्यान में रखते हुए लगभग 500 वाहनों में चार कम्पार्टमेंट की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही डिजिटल व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिससे कचरा संग्रहण वाहनों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि राज्य में प्रतिदिन लगभग 1,930 मीट्रिक टन ठोस कचरा उत्पन्न हो रहा है, जबकि करीब 1,800 मीट्रिक टन कचरे का प्रतिदिन प्रसंस्करण किया जा रहा है। प्लास्टिक कचरे का भी पृथक रूप से प्रसंस्करण किया जा रहा है। कचरा संग्रहण व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 657 नए वाहन खरीदे जा रहे हैं, जिनमें लगभग 480 ई-वाहन भी शामिल हैं। राज्य में वर्तमान में 22 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, लगभग 50 मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी तथा 600 से अधिक वेस्ट कम्पोस्टर संचालित हैं। इस दौरान अधिकारियों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों, जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा आमजन की सामूहिक भागीदारी को आवश्यक बताया।

बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। हरिद्वार-लक्सर रोड हादसों का हब बनता जा रहा है। सिंगल रूट होने के कारण सड़क पर लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव के बीच आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बीती देर रात एक बार फिर पतंजलि फूड पार्क से पहले बिसलेरी प्लांट के पास दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे की सूचना देर रात करीब 108 के माध्यम से पुलिस को मिली। सूचना पर फेरुपुर चौकी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को धनपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में चिकित्सकों ने हिमांशु (20) पुत्र राजकुमार, निवासी रानीमाजरा, थाना पथरी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल विशाल पुत्र अमर सिंह, निवासी घिस्सुपुरा, थाना पथरी की हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हरिद्वार-लक्सर रोड लंबे समय से यातायात के बढ़ते दबाव से जूझ रहा है। सड़क के सिंगल रूट होने के कारण आमने-सामने से गुजरने वाले वाहनों के बीच हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सड़क की क्षमता उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है। ऐसे में इस मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। पथरी थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि 108 के माध्यम से हादसे की सूचना मिली थी। फेरुपुर चौकी की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हिमांशु को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि विशाल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मृतक के परिजनों को सूचना देने के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए हरिद्वार चिकित्सालय भेज दिया है। पुलिस टीम हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया आर्येन्द्र शर्मा का जन्म दिवस

संवाददाता

देहरादून। कांग्रेस नेता आर्येन्द्र शर्मा का जन्मदिवस सहसपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओ ने धूमधाम से मनाया। आज यहां बसंत विहार स्थित आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आर्येन्द्र शर्मा का 57वां जन्म दिवस धमधाम से मनाया। कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य व पूर्व सीएम के ओएसडी आर्येन्द्र शर्मा के जन्म दिवस के अवसर पर उनके आवास पर डीएवी कालेज मे पूर्व पदाधिकारी व कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए। सभी ने शर्मा को जन्म दिवस की बधाई दी। जिसके बाद केक काटने के बाद शर्मा ने सभी की शुभकामनाएं लेकर धन्यवाद किया। बता दें कि आर्येन्द्र शर्मा कांग्रेस पार्टी के जमीन से जुड़े नेता है जिनके कार्यकर्ता उन्हे 2027 के विधानसभा चुनाव में सहसपुर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर देख रहे है। जिनके सामाजिक कार्यो को देखते हुए वहां की जनता भी उन्हे पंसद कर रही है।

डेंगू-मलेरिया रोकथाम को लेकर हुई बैठक, चलेगा सघन अभियान

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। डेंगू, मलेरिया एवं अन्य मच्छरजनित रोगों की रोकथाम को लेकर नगर आयुक्त नंदन कुमार के निर्देश पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पवन कार्की की अध्यक्षता में नगर निगम हरिद्वार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा करते हुए आगामी दिनों में सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम डेंगू-मलेरिया की रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण, लार्वा की जांच एवं नष्ट करने तथा जन-जागरूकता अभियान चलाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखते हुए जलभराव रोकने और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पवन कार्की ने अधिकारियों एवं सफाई निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लार्वा की जांच कर उन्हें नष्ट करने, जलभराव वाले स्थानों को चिन्हित करने तथा घरों एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को बचाव के उपायों की जानकारी देने और पंपलेट वितरित करने को कहा। उन्होंने बताया कि तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, कमजोरी तथा त्वचा पर लाल चकत्ते डेंगू के प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की गई। बैठक के बाद नगर निगम की टीम ने परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षण और जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान रुके हुए पानी तथा मच्छरों के प्रजनन की संभावित जगहों की जांच की गई। घरों एवं प्रतिष्ठानों में रखे गमलों, कूलरों, पुराने बर्तनों और टायरों की भी जांच की गई। बैठक में मुख्य सफाई निरीक्षक विकास चौधरी, संजय शर्मा, श्रीकांत, विकास कुमार, मनोज कुमार, सुनील एवं अर्जुन कुमार तथा सफाई निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, धीरेंद्र सेमवाल, अनिल कुमार, आकाश, रूपाली, मोहित, राहुल, प्रशांत एवं विनय कुमार आदि उपस्थित रहे।

जर्जर भवनों पर डीएम सख्तः चिन्हीकरण के निर्देश

हमारे संवाददाता

देहरादून। जर्जर एवं संभावित रूप से असुरक्षित भवनों के चिन्हीकरण को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बीती देर शाम वर्चुअल बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी भवन को जर्जर अथवा गिरासू घोषित करने से पहले उसके तकनीकी और संरचनात्मक पहलुओं की गहन जांच की जाए। उन्होंने कहा कि भवन की वास्तविक स्थिति का तकनीकी आकलन किए बिना कोई निर्णय न लिया जाए, ताकि जनसुरक्षा के साथ-साथ अनावश्यक कार्रवाई से भी बचा जा सके। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों, नगर निगम एवं नगर पालिका परिषदों के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जर्जर भवनों का प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए। सर्वेक्षण के दौरान भवन की वर्तमान स्थिति, संरचनात्मक मजबूती तथा आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा समेत अन्य आवश्यक पहलुओं का परीक्षण करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने नगर निगम, नगर पालिका परिषदों, लोक निर्माण विभाग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के अधिकारियों को भवनों के तकनीकी निरीक्षण के लिए विशेषज्ञ तकनीकी टीमें गठित करने के निर्देश दिए।

तकनीकी जांच के बाद ही भवन को जर्जर घोषित करें: जिलाधिकारी

उन्होंने विभिन्न विभागों के समन्वय से तकनीकी सर्वेक्षण कर भवनों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भवन को गिरासू घोषित करने की कार्रवाई में तकनीकी और विधिक दोनों पहलुओं का पूरी तरह पालन किया जाए। जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने अधिकारियों को संभावित दुर्घटनाओं और जनहानि को रोकने के लिए समय रहते सुरक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के. के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद सहित कई लोग शामिल रहे।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राचीन अनुसूचित जाति खेड़ा ग्राम समिति पता-चकतुनवाला देहरादून के द्वारा नवीनीकरण हेतू आवेदन किया गया है। यदि इस सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर अपनी आपत्ति कार्यालय निबंधक फर्म्स सोसाइटी एंव चिट्स देहरादून में दर्ज करा सकते है।

अध्यक्ष-तिलक सिंह
निवासी लोअर तुनवाला देहरादून।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकारः
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालयः दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोटः सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।